ADV. RANJANA DIXIT
NATIONAL JOINT SECRETARY
GENERAL CELL [F], (IN)

HELPLINE: +91 8510888811
E-MAIL: INFO@WHRRC.ORG
MEMBERSHIP ID: 0000003124

WORLD HUMAN RIGHTS RESEARCH COUNCIL (WHRRC)

DEDICATED TO HUMAN RIGHTS

SR: 0102092026 **DATE: 02 SEP 2026**

प्रति,
पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश (IN)

विषयउज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान घाट में मृत मानव शरीर के अंश के कथित रूप से सेवन किए : जाने की घटना के संबंध में मानव गरिमा एवं मानवाधिकार के दृष्टिकोण से अनुसंधानात्मक संज्ञान तथा की गई पुलिस कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

विश्व मानवाधिकार अनुसंधान परिषद् (WHRRC) के संज्ञान में उज्जैन से संबंधित एक अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक घटना सामने आई है। विभिन्न सार्वजनिक माध्यमों एवं समाचार रिपोर्टों में सामने आई जानकारी के अनुसार उज्जैन स्थित चक्रतीर्थ श्मशान घाट में एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से जलती हुई चिता से मृत मानव शरीर का अंश निकालकर उसका सेवन किए जाने का वीडियो प्रसारित हुआ है। उपलब्ध समाचार सूचनाओं के अनुसार इस घटना के संबंध में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी सार्वजनिक माध्यमों में सामने आई है। WHRRC इस घटना को अत्यंत गंभीर मानते हुए इसका संज्ञान मुख्यतः मानव गरिमा, मृत मानव शरीर के सम्मान, विधि के शासन, आपराधिक न्याय व्यवस्था तथा मानवाधिकार संरक्षण के व्यापक दृष्टिकोण से ले रहा है।

यह उल्लेख करना आवश्यक है कि परिषद् किसी व्यक्ति की किन्नर/ट्रांसजेंडर पहचान, धार्मिक पहचान, अघोरी परंपरा अथवा किसी विशेष सामाजिक या आध्यात्मिक समुदाय के आधार पर कोई टिप्पणी या कार्रवाई की मांग नहीं कर रही है। परिषद् की चिंता केवल उस कथित कृत्य से संबंधित है जिसमें मृत मानव शरीर अथवा उसके अंश के साथ ऐसा व्यवहार किए जाने की बात सामने आई है, जो यदि जांच में सत्य पाया जाता है, तो मृतक की गरिमा एवं सम्मान के साथ-साथ कानून और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित गंभीर प्रश्न उत्पन्न करता है। किसी व्यक्ति की पहचान से स्वतंत्र होकर प्रत्येक कथित आपराधिक कृत्य का मूल्यांकन उसके वास्तविक तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानून के आधार पर किया जाना मानवाधिकार एवं विधि के शासन का मूल सिद्धांत है।

मानव सभ्यता एवं आधुनिक मानवाधिकार व्यवस्था में मानव गरिमा को सर्वोच्च मूल्यों में स्थान प्राप्त है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी उसके शरीर और मानव अवशेषों के साथ सम्मानजनक व्यवहार का प्रश्न केवल धार्मिक अथवा सामाजिक परंपरा का विषय नहीं है, बल्कि मानव गरिमा और मृतक के सम्मान से जुड़ा गंभीर मानवीय प्रश्न है। मृत व्यक्ति अपने शरीर और सम्मान की स्वयं रक्षा करने की स्थिति में नहीं होता और ऐसी स्थिति में उसके शव की सुरक्षा, सम्मानजनक हैंडलिंग तथा अंतिम संस्कार की गरिमा सुनिश्चित करना राज्य एवं प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। किसी मृत शरीर के साथ जानबूझकर किया गया अपमानजनक या अमानवीय व्यवहार मृतक के परिवार, उसके निकट संबंधियों तथा व्यापक समाज की संवेदनाओं और न्याय संबंधी विश्वास को भी प्रभावित कर सकता है।

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में **अनुच्छेद 21** जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल संवैधानिक आधार है। भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि जीवन के अधिकार को केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके साथ मानव गरिमा का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है। मृत शरीर के सम्मानजनक व्यवहार तथा अंतिम संस्कार की गरिमा से संबंधित न्यायिक दृष्टिकोण भी इसी व्यापक मानवीय गरिमा के सिद्धांत से जुड़ा है। इसलिए प्रस्तुत घटना को केवल सामान्य कानून-व्यवस्था की घटना के रूप में देखने के स्थान पर मृत मानव शरीर की गरिमा और सम्मान के संवैधानिक एवं मानवाधिकार पक्ष को भी जांच में उचित महत्व दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

घटना के आपराधिक पक्ष की दृष्टि से वर्तमान भारतीय दंड व्यवस्था में **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 301** विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि यह अंतिम संस्कार के स्थान तथा मानव शव के साथ अपमान से संबंधित कृत्यों को संबोधित करती है। तथापि, किसी भी कानूनी प्रावधान की वास्तविक प्रयोज्यता घटना के प्रमाणित तथ्यों और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करती है। इसलिए **WHRRC** का सुझाव है कि पुलिस द्वारा घटना के समस्त तथ्यों का निष्पक्ष परीक्षण करते हुए धारा **301** सहित घटना के अनुरूप लागू होने वाले अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों की भी जांच की जाए और यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता अथवा अन्य अपराध के तत्व सामने आते हैं तो उनके संबंध में भी विधि के अनुसार कार्रवाई की जाए।

इस घटना का एक महत्वपूर्ण पक्ष **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)** के व्यापक मानवाधिकार सिद्धांतों से भी संबंधित है। **UDHR** के **Article 1** में सभी मनुष्यों की समान गरिमा और अधिकारों को स्वीकार किया गया है, **Article 3** जीवन एवं व्यक्ति की सुरक्षा, **Article 5** क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण, **Article 7** कानून के समक्ष समानता तथा **Article 8** प्रभावी कानूनी उपचार के सिद्धांत को स्थापित करता है। यद्यपि **UDHR** स्वयं किसी आपराधिक मामले में **FIR** दर्ज करने वाला दंडात्मक कानून नहीं है, लेकिन यह मानव गरिमा, समानता, न्याय एवं प्रभावी संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए मूल सिद्धांतों का महत्वपूर्ण आधार है। इसी दृष्टिकोण से मृत मानव शरीर के साथ सम्मानजनक व्यवहार और घटना की निष्पक्ष जांच को मानव गरिमा के व्यापक सिद्धांत से जोड़कर देखा जाना उचित है।

इसी प्रकार **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993** भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग की वैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत मानवाधिकारों के उल्लंघन अथवा उसके अवप्रेरण तथा ऐसी उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही से संबंधित मामलों की जांच का प्रावधान है। **WHRRC** की दृष्टि में इस घटना का अध्ययन केवल कथित आरोपी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई तक सीमित न रहकर इस व्यापक प्रश्न से भी संबंधित है कि क्या मृत मानव शरीर की गरिमा एवं सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त प्रशासनिक एवं संस्थागत रक्षोपाय उपलब्ध हैं तथा क्या ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी बचाव के उपाय कार्यरत हैं।

मानवाधिकार अनुसंधान के दृष्टिकोण से इस घटना में **वैज्ञानिक एवं साक्ष्य-आधारित जांच** अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि घटना से संबंधित वीडियो अथवा अन्य डिजिटल सामग्री उपलब्ध है तो उसकी वास्तविकता, मूल स्रोत, रिकॉर्डिंग का समय, स्थान, निरंतरता तथा प्रामाणिकता का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार घटनास्थल से संबंधित **CCTV** फुटेज, तस्वीरें, मोबाइल रिकॉर्डिंग तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत को सुरक्षित रखना जांच की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि उपलब्ध हो तो फोरेंसिक सबूत की कस्टडी चेन बनाए रखना और आवश्यकतानुसार फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की सहायता लेना भी प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने में उपयोगी होगा।

मृतक की पहचान, मृत्यु की परिस्थितियों तथा शव की स्थिति का सत्यापन भी इस घटना की संपूर्ण पृष्ठभूमि समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुसंधान की दृष्टि से यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, शव चिता तक किस प्रकार पहुंचा, कथित रूप से शव के साथ हस्तक्षेप किस समय और किन परिस्थितियों में हुआ तथा क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका रही। यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने घटना में सहायता की, उकसाया, रिकॉर्ड किया, साक्ष्य छिपाया या घटना को किसी अन्य आपराधिक उद्देश्य से संचालित किया, तो ऐसे सभी पहलुओं का परीक्षण भी निष्पक्ष जांच का हिस्सा होना चाहिए।

WHRRC का यह भी मानना है कि घटना को किसी व्यक्ति या समुदाय की धार्मिक अथवा सामाजिक पहचान से जोड़कर व्यापक निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। भारत में विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान किया जाना आवश्यक है, परंतु किसी भी परंपरा या व्यक्तिगत पहचान को कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति के कथित कृत्य के आधार पर पूरे किन्नर/ट्रांसजेंडर समुदाय अथवा अघोरी परंपरा को दोषी ठहराना भी मानवाधिकारों के गैर-भेदभाव एवं समानता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। जांच का आधार केवल कथित कृत्य, उपलब्ध साक्ष्य और लागू कानून होना चाहिए।

इस घटना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू **श्मशान स्थल की सुरक्षा एवं निवारक शासन** से संबंधित है। यदि जांच में घटना की पुष्टि होती है, तो यह भी अध्ययन का विषय हो सकता है कि सार्वजनिक श्मशान स्थल पर मृत शरीरों की सुरक्षा, प्रवेश नियंत्रण, निगरानी, **CCTV** व्यवस्था तथा संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं। यदि किसी स्तर पर ऐसी व्यवस्था में गंभीर कमी सामने आती है, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासनिक एवं बचाव के उपाय पर विचार किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार घटना की जांच केवल वर्तमान अपराध तक सीमित न रहकर भविष्य की रोकथाम के लिए भी उपयोगी हो सकती है।

WHRRC का उद्देश्य मानवाधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का तथ्यात्मक दस्तावेज़ीकरण, शोध और विश्लेषण करना तथा ऐसी घटनाओं से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में मानव गरिमा एवं मानवाधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए अध्ययन एवं सुझाव तैयार करना है। इसी कारण इस प्रकरण में पुलिस द्वारा की गई वास्तविक एवं प्रमाणित कार्रवाई का विवरण परिषद् के अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अतः **WHRRC** की ओर से यह **सुझाव एवं अपेक्षा** व्यक्त की जाती है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट परिषद् को उपलब्ध कराई जाए, जिसमें यदि **FIR/Crime Number** दर्ज किया गया है तो उसका क्रमांक एवं दिनांक, संबंधित थाना, लागू की गई धाराएं, आरोपी के विरुद्ध की गई कार्रवाई, गिरफ्तारी की स्थिति, जांच अधिकारी का पदनाम, घटनास्थल से प्राप्त प्रमुख साक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण, उपलब्ध **CCTV** अथवा डिजिटल सबूत की जांच की स्थिति, फोरेंसिक जांच की स्थिति तथा प्रकरण की वर्तमान जांच स्थिति का उल्लेख किया जा सके।

यदि जांच अभी जारी है, तो वर्तमान स्थिति के अनुरूप उपलब्ध जानकारी एवं अब तक की गई प्रमुख कार्रवाई का विवरण उपलब्ध कराया जाना अनुसंधान की दृष्टि से पर्याप्त होगा तथा जांच पूर्ण होने के पश्चात अंतिम जांच निष्कर्ष एवं की गई वैधानिक कार्रवाई से संबंधित अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जा सकती है। **WHRRC** इस जानकारी का उपयोग केवल मानवाधिकार अनुसंधान, केस से संबंधित दस्तावेज़, संस्थागत अध्ययन तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम से संबंधित अध्ययन के उद्देश्य से करेगा।

परिषद् का मानना है कि इस प्रकार की घटना पर निष्पक्ष, वैज्ञानिक और कानूनसम्मत कार्रवाई न केवल संबंधित प्रकरण में न्याय की दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि इससे समाज में विधि के शासन, मानव गरिमा तथा न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को भी मजबूती मिलती है। साथ ही, ऐसी घटनाओं की तथ्यात्मक जांच और उनका उचित प्रलेखन भविष्य में मानवाधिकार नीति, शव-सुरक्षा व्यवस्था तथा बचाव के उपाय को बेहतर बनाने में उपयोगी हो सकता है।

अतः WHRRC इस प्रकरण को **मानव गरिमा एवं मृत मानव शरीर के सम्मान से संबंधित गंभीर अनुसंधानात्मक विषय** के रूप में अपने अभिलेख में संज्ञानित कर रहा है तथा पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा करता है, ताकि परिषद् इस घटना का मानवाधिकार, कानूनी एवं अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण से निष्पक्ष अध्ययन कर सके। **आप अपनी विस्तृत रिपोर्ट हमें ईमेल के माध्यम से info@whrrc.org पर भेज सकते हैं।**

भवदीया,

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन, मध्य प्रदेश।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश।
3. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, उज्जैन।
4. मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
5. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली।

भवदीया,

अधिवक्ता रंजना दीक्षित
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव

ADV. RANJANA DIXIT
NATIONAL JOINT SECRETARY
GENERAL CELL [F], (IN)

HELPLINE: +91 8510888811
E-MAIL: INFO@WHRRC.ORG
MEMBERSHIP ID: 0000003124

WORLD HUMAN RIGHTS RESEARCH COUNCIL (WHRRC)

DEDICATED TO HUMAN RIGHTS

SR: 0102092026 **DATE: 02 SEP 2026**

To,
The Superintendent of Police
District Ujjain, Madhya Pradesh (IN)

Subject: Regarding the incident of alleged consumption of a portion of a deceased human body at Chakratirth Cremation Ground, Ujjain, taking cognizance from the perspective of human dignity and human rights, and providing a detailed report of the police action taken.

Sir/Madam,

A very serious and concerning incident relating to Ujjain has come to the notice of the World Human Rights Research Council (WHRRC). According to the information appearing through various public sources and news reports, a video has been circulated in which a person allegedly took a portion of a deceased human body from a burning funeral pyre at Chakratirth Cremation Ground, Ujjain, and consumed it. According to the available news information, it has also come into the public domain that the police have registered a case in connection with the incident and have taken action against the concerned person. WHRRC, considering this incident to be extremely serious, is taking cognizance of the matter primarily from the broader perspective of human dignity, respect for the deceased human body, the rule of law, the criminal justice system, and the protection of human rights.

It is necessary to mention that the Council is not seeking any comment or action on the basis of the person's Kinnar/Transgender identity, religious identity, Aghori tradition, or any particular social or spiritual community. The concern of the Council is limited only to the alleged act in which the deceased human body or a portion thereof is stated to have been treated in such a manner which, if found to be true during the investigation, raises serious questions relating to the dignity and respect of the deceased as well as law and public order. Independent of the identity of any person, evaluating every alleged criminal act on the basis of its actual facts, available evidence, and applicable law is a fundamental principle of human rights and the rule of law.

Human dignity occupies a place among the highest values in human civilization and the modern human rights system. Even after a person's death, the issue of respectful treatment of the body and human remains is not merely a matter of religious or social tradition, but is a serious humanitarian issue connected with human dignity and respect for the deceased. A deceased person is not in a position to protect his or her own body and dignity, and in such circumstances, ensuring the safety of the body, its respectful handling, and the dignity of the final rites becomes an important responsibility of the State and administration. Deliberate disrespectful or inhuman treatment of a deceased body may also affect the sentiments of the family of the deceased, their close relatives, and the broader society, as well as their confidence in justice.

Under the Indian constitutional system, **Article 21** is the fundamental constitutional basis for the protection of life and personal liberty. The Indian judiciary has, from time to time,

clarified that the right to life cannot be restricted merely to physical survival, but is also connected with the principle of human dignity. The judicial approach relating to respectful treatment of a dead body and the dignity of the last rites is also connected with this broader principle of human dignity. Therefore, instead of viewing the present incident merely as an ordinary law-and-order matter, it appears necessary that the constitutional and human rights aspects relating to the dignity and respect of the deceased human body should also be given due importance during the investigation.

From the criminal aspect of the incident, **Section 301 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023** is particularly relevant under the present Indian criminal law framework, as it addresses acts relating to places of funeral rites and indignity to a human corpse. However, the actual applicability of any legal provision depends upon the established facts of the incident and the evidence that emerges during the investigation. Therefore, WHRRC suggests that the police conduct an impartial examination of all the facts of the incident, including the applicability of Section 301 and other relevant legal provisions applicable to the facts of the case, and if the involvement of any other person or elements of any other offence emerge during the investigation, appropriate action may also be taken in accordance with law.

An important aspect of this incident is also related to the broader human rights principles of the **Universal Declaration of Human Rights (UDHR)**. Article 1 of the UDHR recognizes the equal dignity and rights of all human beings; Article 3 concerns life and security of person; Article 5 provides protection against cruel, inhuman or degrading treatment; Article 7 establishes equality before the law; and Article 8 establishes the principle of an effective legal remedy. Although the UDHR itself is not a penal law providing for registration of an FIR in a criminal case, it constitutes an important foundation of internationally recognized principles concerning human dignity, equality, justice, and effective protection. From this perspective, respectful treatment of a deceased human body and an impartial investigation of the incident may appropriately be viewed in connection with the broader principle of human dignity.

Similarly, the **Protection of Human Rights Act, 1993** provides the statutory framework in India for the protection of human rights through the National Human Rights Commission and State Human Rights Commissions. The Act provides for inquiry into matters relating to violations of human rights or abetment thereof and negligence in the prevention of such violations. From the perspective of WHRRC, the study of this incident should not be limited only to criminal action against the alleged accused, but should also relate to the broader question of whether adequate administrative and institutional safeguards are available at the local level for the dignity and protection of deceased human bodies and whether effective preventive measures are functioning to prevent such incidents.

From the perspective of human rights research, **scientific and evidence-based investigation** in this incident is extremely important. If any video or other digital material relating to the incident is available, it is necessary that its authenticity, original source, time of recording, location, continuity, and genuineness be scientifically examined. Similarly, preserving CCTV footage, photographs, mobile recordings, and other electronic evidence relating to the place of occurrence may be important for the credibility of the investigation. If available,

maintaining the chain of custody of forensic evidence and obtaining assistance from the Forensic Science Laboratory, wherever necessary, may also be useful in establishing the factual position of the case.

Verification of the identity of the deceased, the circumstances of death, and the condition of the body is also important for understanding the complete background of the incident. From the research perspective, it is necessary to establish under what circumstances the concerned person died, how the body reached the funeral pyre, at what time and under what circumstances the alleged interference with the body took place, and whether any other person had any direct or indirect role in the incident. If the investigation establishes that any other person assisted in the incident, instigated it, recorded it, concealed evidence, or conducted the incident for any other criminal purpose, all such aspects should also form part of an impartial investigation.

WHRRC also believes that it would not be appropriate to draw broad conclusions by linking the incident with the religious or social identity of any individual or community. In India, various religious, spiritual, and cultural traditions must be respected; however, no tradition or individual identity can be considered above the law. Similarly, holding the entire Kinnar/Transgender community or the Aghori tradition responsible on the basis of the alleged act of one individual would also not be consistent with the principles of non-discrimination and equality under human rights. The investigation should be based solely on the alleged act, available evidence, and applicable law.

Another important aspect of this incident relates to **the security and preventive governance of the cremation site**. If the incident is confirmed during the investigation, it may also become a subject of study as to how the security of deceased bodies, access control, surveillance, CCTV arrangements, and related administrative arrangements are being operated at the public cremation ground. If any serious deficiency in such arrangements emerges at any level, administrative and preventive measures should be considered to prevent recurrence of such incidents in the future. In this manner, the investigation of the incident may not remain limited only to the present offence but may also be useful for future prevention.

The objective of WHRRC is to carry out factual documentation, research, and analysis of important incidents relating to human rights and, on the basis of the findings arising from such incidents, to prepare studies and suggestions for better protection of human dignity and human rights in the future. For this reason, the details of the actual and verified action taken by the police in this matter are extremely important for the research of the Council.

Therefore, on behalf of WHRRC, this **suggestion and expectation** is being expressed that a detailed factual report of the action taken by the police so far in the matter may be made available to the Council, including, if an FIR/Crime Number has been registered, its number and date, the concerned police station, the sections applied, the action taken against the accused, the status of arrest, the designation of the Investigating Officer, a brief description of the major evidence obtained from the place of occurrence, the status of examination of available CCTV or digital evidence, the status of forensic examination, and the present status of the investigation.

ADV. RANJANA DIXIT
NATIONAL JOINT SECRETARY
GENERAL CELL [F], (IN)

HELPLINE: +91 8510888811
E-MAIL: INFO@WHRRC.ORG
MEMBERSHIP ID: 0000003124

WORLD HUMAN RIGHTS RESEARCH COUNCIL (WHRRC)

DEDICATED TO HUMAN RIGHTS

If the investigation is still in progress, providing the available information according to the present status and details of the major action taken so far would be sufficient from the research perspective, and after completion of the investigation, the final investigation findings and updated information regarding the statutory action taken may also be provided. WHRRC will use this information solely for the purposes of human rights research, case-related documentation, institutional study, and study relating to the prevention of such incidents in the future.

The Council believes that impartial, scientific, and lawful action in such an incident is necessary not only from the perspective of justice in the concerned case, but also for strengthening public confidence in the rule of law, human dignity, and the justice system. At the same time, factual investigation and proper documentation of such incidents may be useful in the future for improving human rights policy, protection arrangements for deceased bodies, and preventive measures.

Therefore, WHRRC is taking cognizance of this matter in its records as a **serious research subject relating to human dignity and respect for the deceased human body** and expects that a detailed factual report of the action taken by the police administration may be made available, so that the Council may conduct an impartial study of this incident from the human rights, legal, and research perspectives. **You may send your detailed report to us via email at info@whrrc.org**

Yours faithfully,

Copy for information to:

1. Inspector General of Police, Ujjain Zone, Madhya Pradesh.
2. Director General of Police, Madhya Pradesh.
3. Collector and District Magistrate, Ujjain.
4. Madhya Pradesh Human Rights Commission, Bhopal.
5. National Human Rights Commission, New Delhi.

Yours faithfully,

Advocate Ranjana Dixit
National Joint Secretary